VISION IAS

www.visionias.in

07 SEP 2019

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1247)

Name of Candidate	Bhanu Pratap Singh		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	635609
Center	MN, Delhi	Date	07-09-19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Mention the structure and functions of NITI Aayog. Also, comment on its contemporary relevance. **(150 words) 10**

नीति (NITI) आयोग की संरचना और प्रकार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी टिप्पणी कीजिए।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। यह भारत सरकार का प्रमुख 'थिंक टैंक' है।

संरचना

- अध्यक्ष → प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष
- पूर्णकालिक सदस्य
- अंशकालिक सदस्य
- CEO

↓

शासी परिषद → राज्यों के मुख्यमंत्री + UTs के राज्यपाल

प्रकार्य – नीति आयोग के प्रकार्य इस प्रकार हैं:–

- विकास एवं योजनाओं का खाका बनाना।
- 'सहकारी संघवाद' की अवधारणा को मजबूत करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ज्वलंत मुद्दों के संबंध में सरकार को सलाह देना जैसा - पर्यावरण, कृषि, e-vehicles
- माँग आधारित विकास नीतियाँ बनाना।

समकालीन प्रासंगिकता

⇒ वर्तमान में विकास हेतु 'Bottom to Top' एप्रोच की आवश्यकता है। आयोग इस कार्य को बखूबी निभा रहा है।

⇒ राज्यों की भिन्न-भिन्न भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप के 'विकास मॉडल' की अनुशंसा करता है।

⇒ 'सहकारी संघवाद' वर्तमान आवश्यकता है। आयोग 'गवर्निंग काउंसिल' में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

कुल मिलाकर वर्तमान समस्याओं के आलोक में नीति आयोग प्रासंगिक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Critically discuss the practice of setting up Fast Track Courts to reduce pendency of cases in the judiciary. **(150 words) 10**

न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

नीति आयोग की 'Strategy for New India@75' रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लंबित मामलों का निपटान लगभग 365वर्षों में होगा।

इसी कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) की अवधारणा आती है। FTC अपने प्रकृति में गंभीर मामलों को समय व तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई करते है ताकि मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके।

इनकी स्थापना की मूल में विलंबित मामलों की कमी तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था

FTC ने हत्या, बलात्कार, दहेज इत्यादि मामलों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन कमजोर आधारभूत संरचना, न्यायधीशों की कम ~~स्थल~~ संख्या, बार-बार स्थगन, पुलिस तंत्र द्वारा जाँच में देरी इत्यादि कारणों से FTC की धारणा धूमिल होती जा रही है।

इनमें भी मामलों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या चिंता का विषय है।

इसी कारण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 'जीरो पेंडेंसी केस' अभियान चलाया गया है।

कुल मिलाकर IT का प्रयोग, न्यायधीशों की त्वरित नियुक्ति, इत्यादि नूतन पहलों से FTC की कार्यप्रणाली को त्वरित किया जा सकता है।

3. Highlight the challenges faced by lower judiciary in India and suggest measures for enhancing their productivity. **(150 words) 10**

भारत में निचली अदालतों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में त्रिस्तरीय एकीकृत न्याय प्रणाली है। निचली अदालतें निम्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं:—

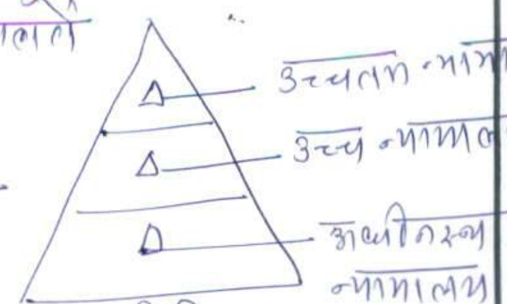

[1] न्यायाधीशों की कम संख्या - विधि आयोग के अनुसार भारत में न्यायधीश: जनसंख्या अनुपात 1 लाख : 20 है, जो (1 लाख : 50) होना चाहिए।

[2] आधारभूत ढाँचे का कमजोर होना निचली अदालतों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।

[3] बार-बार स्थगन भी लंबित मामलों की संख्या को बढ़ा रहे हैं।

[4] योग्य व कुशल न्यायाधीशों की कमी भी एक अन्य चुनौती है।

[5] इसके अलावा लीगल एजुकेशन हेतु 'रीडिंग कल्चर' का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निचली अदालतों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपाय निम्नांकित हैं :-

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का गठन किया जाए।
- आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने हेतु सरकारी निवेश बढ़ाया जाए।
- IT का प्रयोग करके उत्पादकता बढ़ायी जाए। यथा- ई-फाइलिंग
- न्यायधीशों को प्रशिक्षण एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विधि ज्ञान व शब्दावली का एक ही स्थान पर स्थानीकरण।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना पर बल।
- साथ ही साथ मध्यस्थता पर बल

कुल मिलाकर "न्याय में देरी अन्याय होती है" को ध्यान में रखकर निचली अदालतों की उत्पादकता बढ़ाना वर्तमान समय की मांग है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Assess the need to formalise the process of post-legislative scrutiny to improve the effectiveness of laws. **(150 words) 10**

कानूनों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए विधि-निर्माण पश्चात् संवीक्षा की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स-19 में भारत का 68 वाँ स्थान है।

कानून की प्रभावशीलता हेतु दो पक्ष हैं – प्रथम - विधि निर्माण तथा द्वितीय - संवीक्षा प्रक्रिया → औपचारिकरण

- सर्वप्रथम ऐसी विधि निर्मित करनी चाहिए जो वर्तमान समय की समस्याओं के साथ-साथ भविष्य की चिंताओं का भी समाधान करे। 2nd ARC के अनुसार कानून सरल व पारदर्शी होना चाहिए।

- विधि-निर्माण के बाद इसकी समीक्षा जरूरी है। लेकिन समीक्षा तंत्र औपचारिक होना चाहिए। उदा० के लिए कोई न्यायाधीशों, कानूनविदों एवं विशेषज्ञों की कमेटी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ऐसा होने पर कानून को जीवंत एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकता है। उदा० के लिए वर्तमान में औपनिवेशिक कालीन अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा रहा है।

- लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि विधि की समीक्षा इतनी भी औपचारिक नहीं होनी चाहिए कि उसमें आम-जनता की राय तथा NGOs, सिविल समाज का सहयोग पीछे छूट जाए।

कुल मिलाकर विधि निर्माण के पश्चात् समीक्षा का औपचारिकरण लेटलतीफी से मुक्ति, जीवंतता एवं सहयोग सुनिश्चित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the potential of Artificial Intelligence (AI) in improving the effectiveness of e-governance in India. **(150 words) 10**

भारत में ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता की विवेचना कीजिए।

ई - गवर्नेंस से तात्पर्य है कि शासन में IT का प्रयोग ताकि दक्षता, प्रभावशीलता, मितव्ययता के साथ नीतियों का कार्यान्वयन किया जा सके ।

AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ई - गवर्नेंस की प्रभावशीलता में निम्न प्रकार सुधार ला सकती है : —

- रोबोटिक्स की मदद ह्यूमनाइड मानव की तरह कार्य करते है।
- आँकड़ों के विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- इस संबंध में "बिग डाटा एनालिसिस" भी शासन संबंधी गतिविधियों के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

योगदान दे रहा। यथा- ट्रैफिक उल्लंघन के डाटा का विश्लेषण करके सुरक्षित सड़क नीतियाँ जारी की जा सकती हैं।

- IOT, DLT की मदद से भ्रष्टाचार नियंत्रण, विके-न्द्रीकरण इत्यादि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि DLT में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है।

- AI की मदद से स्वास्थ्य नीतियों में भी प्रभावशीलता लायी जा सकती है।

अतः AI का प्रयोग हि गवर्नेंस को त्वरित करेगा लेकिन विवेक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

6. Despite various reforms in the public grievance redressal mechanisms, their effectiveness remain limited. Discuss. **(150 words) 10**

लोक शिकायत निवारण प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। चर्चा कीजिए।

लोगों की शिकायतों के निवारण एवं त्वरित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से लोक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई।

इसमें अनेक सुधार क्रमा — IT प्रयोग, सेवोत्तम मॉडल, ई-क्रांति इत्यादि प्रयोग किए गए परंतु इसकी प्रभावशीलता व्यापक नहीं हो पायी है —

- त्वरित मामलों के निपटान हेतु सक्षम शिकायत तंत्र का अभाव प्रमुख बाधा है।
- जन-जागरूकता का अभाव।
- सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सार्वजनिक सहयोग की कमी।
- नवीन आधुनिक तकनीकों का समावेशन नहीं होना।

समाधान

- इसे जनकेन्द्रित बनाया जाए।
- इस हेतु IT का प्रभावी प्रयोग
- लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही
- मीडिया, नागरिक समाज की मदद से जनजागरूकता

अतः वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है, जब उसमें प्रभावी लोक शिकायत निपटान प्रणाली हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Explaining the factors that contribute to trafficking of women and children in India, highlight the steps taken in recent times to combat it. **(150 words) 10**

भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए, इससे निपटने के लिए हाल के दिनों में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बलात श्रम का निषेध है। लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी होती है।

कारण

⇒ संगठित अपराध में संलग्न लोगों द्वारा भौतिक लाभ की चाह।

⇒ खुफिया एजेंसियों एवं पुलिस तंत्र में समन्वय का अभाव

⇒ कम उम्र के बच्चों की सेक्स की मांग

⇒ मानव अंगों की तस्करी → अवैध व्यापार

⇒ आधुनिक दासता में लाभ → वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी 'global slavery Index 2018' में भारत का 53 वां स्थान / 167 देशों में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निपटने हेतु उठाए गए कदम:-

⇒ मानव तस्करी (रोकथाम एवं निवारण) अधि. 2019 में कठोर प्रावधान

⇒ NGOs, नागरिक समाज द्वारा आंदोलन ⇒ जन-जागरूकता।

⇒ ऑनलाइन पोर्टल एवं एप का शुभारंभ

⇒ पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन स्माइल'

⇒ फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।

अतः एक कुशल समाज में मानव तस्करी जैसे कृत्य होना नहीं देता। इसीलिए कठोर कदमों की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. With Vector-Borne Diseases (VBDs) reaching epidemic proportions in India, highlight the factors that have led to their emergence. Also, suggest some measures for their effective control and management. **(150 words) 10**

भारत में रोगाणुवाहक-जनित रोग (VBDs) महामारी की तरह उभरकर सामने आये हैं, अतः उन कारकों को रेखांकित कीजिए जिनके कारण इनका उद्भव हुआ है। साथ ही, इनके प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए।

वेक्टर बोर्न डिजीज वर्तमान समय में महामारी का रूप धारण कर रहे हैं। इसके कारक निम्नांकित हैं:—

- साफ-सफाई का अभाव रोगवाहकों जैसे मच्छर व मक्खियों इत्यादि को पनपने का मौका देता है।
- जलवायु परिवर्तन व तापमान वृद्धि भी इसका एक कारण है।
- अस्वस्थ जीवन शैली तथा माइक्रोबैक्टीरियल रेजीम
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी।
- वैश्वीकरण के कारण अंत:क्रिया का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तीव्र होना।

प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु उपाय

⇒ WASH (वाटर सैनीटेशन एवं हाइजीन) - WHO योजना पर फोकस।

⇒ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार पूरा ट्रीटमेंट।

⇒ नवीन एंटीबायोटिकों की खोज को प्रोत्साहन

⇒ वाहकों को समाप्त करने हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग यथा - मच्छरों का वंध्याकरण।

निष्कर्षतः रोगाणु जनित रोग (VBDs) पर नियंत्रण आवश्यक है। इस हेतु WHO के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है तभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. After years of neglect, rapidly evolving regional strategic realities are now forcing India and Indonesia to coordinate their policies ever more closely. Discuss. **(150 words) 10**

वर्षों की उपेक्षा के बाद, तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताएं अब भारत और इंडोनेशिया को और अधिक घनिष्ठता से अपनी नीतियों को समन्वित करने के लिए बाध्य कर रही हैं। चर्चा कीजिए।

भारत के लिए इंडोनेशिया द. पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।

⇒ इंडोनेशिया द्वारा 'सबांग बंदरगाह' को भारत हेतु देना एक महत्वपूर्ण पहल है।

⇒ इसके अलावा 'आसियान' (ASEAN) में भारत + इंडोनेशिया महत्वपूर्ण सहयोगी है।

⇒ भारत की इंडोनेशिया के प्रति 'आउटरीच डिप्लोमेसी' प्रभावी हो रही है।

⇒ दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संतुलित करने हेतु तत्पर हैं।

⇒ दोनों देशों के मध्य व्यापार, सैन्य व रक्षा सहयोग उच्चतम स्तर पर है।

⇒ हाल ही में भारत इंडोनेशिया में भूकंप व सुनामी पीड़ितों की मदद हेतु "ऑपरेशन मैत्री" चलाया गया, जो दोनों देशों को घनिष्ठ बनाने में सहायक है।

अतः दोनों देशों को वर्तमान समस्याओं के समाधान संबंध प्रगाढ़ करने चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Despite several attempts at resetting the ties, various barriers continue to be a cause of concern in the India-Nepal bilateral relations. Discuss.

(150 words) 10

संबंधों को पुन: स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद, भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न अवरोध निरंतर चिंता का कारण बने हुए हैं। चर्चा कीजिए।

भारत-नेपाल संबंधों का आधार मूल रूप से 'रोटी-बेटी' का रहा है। लेकिन वर्तमान समय में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा की गई यात्राएं एवं सहयोग के बावजूद अवरोध बने हुए हैं! —

⇒ नेपाल को लगता है कि भारत 'बिग ब्रदर सिंड्रोम' से ग्रस्त है वहीं भारत को चीन-नेपाल नजदीकियां चुभती है।

⇒ संविधान निर्माण के समय मधेशी समुदाय का आंदोलन भी दोनों देशों संबंधों में बड़ा अवरोध बना।

⇒ चीन द्वारा नेपाल में अवसंरचनात्मक

प्रोजेक्टों में निवेश भी भारतीय चिंताओं का कारण है।

⇒ इसके अलावा महाकाली नदी विवाद तथा भारत नेपाल मैत्री संधि पर भी चिंताएं हैं।

समाधान

दोनों देशों को निरंतर संवाद स्थापित करते रहना चाहिए।

अतः हम अपने दोस्त बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं की अवधारणा से ओत-प्रोत भारत-नेपाल को अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Delineate the differences between pressure groups and interest groups. Citing examples, elaborate on the ways in which pressure groups influence government decisions and policy making in India. **(250 words) 15**

दबाव समूहों और हित समूहों के मध्य अंतर का वर्णन कीजिए। उदाहरणों को उद्धृत करते हुए, उन तरीकों का सविस्तार वर्णन कीजिए जिनके माध्यम से दबाव समूह भारत में सरकारी निर्णयों और नीति-निर्माण को प्रभावित करते हैं।

दबाव समूह और हित समूह दोनों सरकारी अंगों से इतर सरकारी नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करते हैं।

दोनों के मध्य अंतर इस प्रकार है :-

दबाव समूह	हित समूह
• ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं।	• ये सामान्यतः अनौपचारिक होते हैं।
• इनके गठन में समानता हो भी सकती है और नहीं भी।	• इनके गठन में प्रायः समानता होती है।
• ये संवैधानिक प्रयासों की मदद से नीति	• ये कभी-कभी गैर-कानूनी तरीके भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परिवर्तन पर बल देते हैं।	अपना लेते हैं।
• फिक्की, एसोचैम इत्यादि।	• छात्र संगठन, अनौपचारिक मजदूर संगठन

दबाव - समूहों द्वारा सरकारी नीतियों एवं निर्णयों को निम्न प्रकार/ प्रभावित तरीकों से किया जाता है :→

• आंदोलन के द्वारा दबाव - समूह अपनी मांगों को मनवाते हैं। उदा० के लिए नीतियोग द्वारा पर्यावरण संबंधी आंदोलन।

• हड़ताल एवं धरना - प्रदर्शन द्वारा ये सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। उदा० के लिए विभिन्न व्यापार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संगठनों द्वारा की जाने वाली हड़तालें।

- ये याचिका, हस्ताक्षर अभियान एवं वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने पक्ष में सरकारी नीतियों पर दबाव डालते हैं। उदा० के लिए अनेक पर्यावरण संगठन ऐसे कार्यों में संलग्न पाये जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका प्रभावी उदाहरण है।

- इसके अलावा कभी-कभी लॉबिंग जैसी नकारात्मक धारणाओं के बल पर भी ये सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य है कि भारत में लॉबिंग की अनुमति नहीं है।

कुल मिलाकर दबाव-समूह भारतीय राजनीति अंतराफलक हैं, जो सरकार पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से दबाव डालते हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Highlighting the issues faced by the institutions of local self governance in India, suggest measures that can be taken to improve their effectiveness in the delivery of public goods and services at the grassroot level.

(250 words) 15

भारत में स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं द्वारा समाना की जा रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, जमीनी स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता में सुधार लाने हेतु किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया।

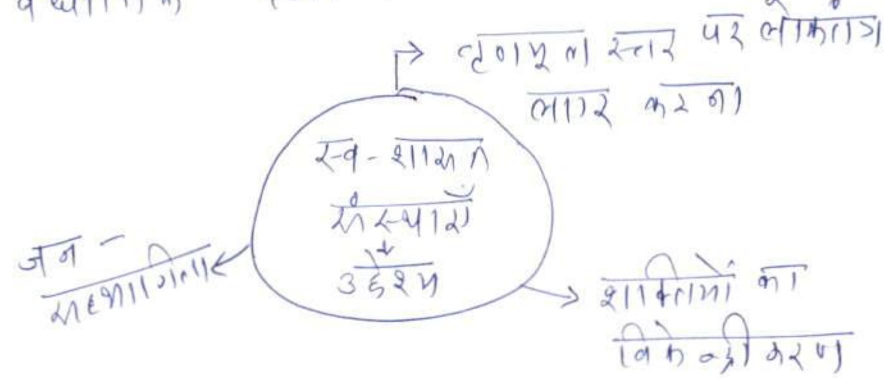

इन स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है :-

- भ्रष्टाचार— ये संस्थाएँ भ्रष्टाचार के कारण प्रभावी रूप से कार्यकुशल नहीं हैं।

- महिलाओं को भले ही 33% आरक्षण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हो परंतु उनके निर्णयों में पुरुष सदस्यों (पति, भाई, पिता) की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है।

• नियमित पर सोशल ऑडिट न हो पाने से संसाधनों की प्रभावशीलता व दक्षता तथा पारदर्शिता का अभाव।

• इसके अलावा जागरूकता का अभाव होने से निम्न वर्ग का शामिल न हो पाना।

• SC/ST वर्ग को उच्च वर्ग द्वारा आरक्षण स्तर सीटों पर लड़ने से रोकना।

• सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का अप्रभावी वितरण।

इसीलिए जमीनी स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता में सुधार लाने हेतु उपाय निम्नांकित हैं:—

• सोशल मीडिया, गैर सरकारी संगठनों (NGO) नागरिक समाज की मदद से जागरूकता फैलाना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्यों द्वारा अधिक शक्तियों का इन संस्थाओं को हस्तांतरण।

- आय व धन हेतु नवीन अवसरों का सृजन। इस हेतु नवीन स्रोतों की पहचान करना।

- IT एवं सोशल ऑडिट के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक।

- पुनरीक्षण तंत्र की स्थापना ताकि सेवाओं की विश्वसनीयता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच की जा सके।

- JAM (जनधन - आधार - मोबाइल) तथा DBT का ठोस कार्यान्वयन।

इस प्रकार जमीनी स्तर प्रभावशीलता एवं सतत लोकतंत्र सुनिश्चित करने हेतु स्वशासी संस्थाओं को मजबूत करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The recent amendment to the Right to Information Act, 2005 will weaken the act and undermine the authority of Information Commissioners. Discuss. **(250 words) 15**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में हालिया संशोधन इस अधिनियम को कमजोर बनाएगा और सूचना आयुक्तों के प्राधिकार को क्षीण करेगा। चर्चा कीजिए।

सूचना का अधिकार अधि०, 2005 (RTI Act, 2005) खुलेपन एवं नागरिक सशक्तीकरण हेतु लाया गया।

RTI Act, 2005
→ पारदर्शिता (नीतियों में)
→ जवाबदेहिता (अधिकारियों की)
→ जन-सहभागिता
→ नागरिकों का सशक्तिकरण

हालिया संशोधन (सूचना अधिकार (संशोधन) अधि 2019) इस प्रकार है:—

- मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) एवं अन्य सूचना आयुक्त (IC) का कार्यकाल अब केन्द्र सरकार सुनिश्चित करेगी। पूर्व में यह 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित था।

- अब CIC व IC का वेतन व भत्ते

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की सरकार तय करेगी। पूर्व में यह मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त के समान थे।

प्रभाव

- कार्यकाल की सुरक्षा न होने CIC व IC निर्भय एवं निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाएंगे।

- वेतन - भत्तों में असमानता परिवर्तन भी उनकी निष्पक्षता व कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा।

- इसके कारण आवश्यक सूचना जो सरकार के अनुकूल नहीं है, देने से मना कर दी जा सकती है।

- इससे मूल अधि. (RTI Act 2005) का मूल उद्देश्य ही संकट में पड़ जाएगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन सरकार का संशोधन के पक्ष में तर्क है कि चूँकि CIC कानूनी संस्था है, वहीं CEC संवैधानिक (Art 324) इसीलिए दोनों की तुलना करना ठीक नहीं है।

इसके अलावा अपील संबंधी विवाद को भी संशोधन हेतु आवश्यक माना गया है।

कुल मिलाकर सूचना आयुक्तों को स्वतंत्र व निर्भय होकर काम करने हेतु अवसर सुनिश्चित करने चाहिए तथा उन्हें कार्यकाल एवं वेतन-भत्तों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस हेतु उनके वेतन संचित निधि पर भारित अथवा घोषित किए जा सकते हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight the process of delimitation in India. Also, throw light on the debates surrounding the delimitation exercise in India. **(250 words) 15**

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। साथ ही, भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर होने वाले वाद-विवादों पर भी प्रकाश डालिए।

भारतीय संविधान में परिसीमन हेतु प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया।

प्रक्रिया

- प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर परिसीमन आयोग का गठन होना चाहिए।
- भारत के राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं।
- इसमें चुनाव आयोग भी मदद करता है। जनगणना के पश्चात सीटों को पुनः समायोजित किया जाता है। समायोजन का आधार जनसंख्या का अनुपात व संख्या होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर होने वाले वाद-विवाद इस प्रकार हैं:—

- चूँकि परिसीमन आयोग के निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फलतः इसकी प्रक्रिया को विपक्षी पार्टियों द्वारा हमेशा संदेह की नजर से देखा जाता है।

- चूँकि जब परिसीमन आयोग की सिफारिशें संसद के पटल पर रखी जाती हैं तो इनमें कोई भी संशोधन मान्य नहीं होता है। अतः इसे लेकर भी वाद-विवाद होता है।

- दक्षिण भारतीय राज्यों (जिन्होंने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण काम किया है। द्वारा भी परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति उठायी जाती है। क्योंकि उनकी संसदीय सीटें कम होने का खतरा है।

• इसके इसका आनुपातिक सिद्धांत (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में) भी विवादित है।

इसीलिए वर्तमान परिसीमन आयोग के गठन में विलंब हुआ तथा सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक स्थिर किया गया है।

सार यही है कि परिसीमन आयोग को समावेशी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु गठन पूर्व चर्चा एवं सर्वसहमति की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत हों।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Self Help Groups (SHGs) are vehicles of rural development, which help in the upliftment of marginalized groups. Elucidate. Further, mention the constraints faced by SHGs and how they can be addressed. **(250 words) 15**

स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण विकास के वाहक हैं तथा ये हाशिए पर मौजूद समूहों के उत्थान में सहायता करते हैं। स्पष्ट कीजिए। साथ ही, SHGs द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का उल्लेख कीजिए। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह (SHGs) छोटे-छोटे समान हितों की पूर्ति हेतु संगठन हैं, जो अपनी छोटी-छोटी बचतों को एक साथ लाकर लाभकारी व्यवसाय करते हैं।

SHGs ग्रामीण विकास के वाहक एवं हाशिए पर मौजूद समूहों के उत्थान में सहायक :—

ग्रामीण विकास

- छोटी-छोटी बचतें बड़ी बचतों में तब्दील।
- ग्रामीण अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम।
- गैर कृषि रोजगार सृजन।

हाशिए पर मौजूद समूह का उत्थान

- वे समूह हैं जिन्हें बैंक सीधे तौर पर गारंटी के रूप्य देने को बचता है।
- इनकी सारी आवश्यकताओं को SHGs

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पूरा करता है।

सशक्तीकरण

SHGs द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएँ इस प्रकार हैं :-

- संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त ऋण की आपूर्ति न होने से गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।
- ब्याज की उच्च दरें लागत बढ़ा देती हैं।
- जोखिम के प्रति बीमा उपायों के विषय में जागरूकता नहीं होने से आकस्मिक जोखिमों का सामना SHGs कर रहे हैं।
- कानूनी ढाँचे के अभाव में कभी-कभी आपसी विवाद भी इनकी प्रगति में बाधा पहुँचाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बाधाओं के समाधान हेतु निम्न उपाय हैं:—

- निम्न व वहनीय दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रो. युनुस के 'बांग्लादेश मॉडल' का उपयोग
- सोशल मीडिया तथा नागरिक समाज व NGOs की मदद से जागरूकता।
- तकनीक एवं कौशल की मदद सरकार उपलब्ध कराये।
- छोटी-छोटी बचतों को बड़ी बचतों में तब्दील करने हेतु बचत की आदत पर बल देने की जरूरत है।

अतः स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण विकास एवं महिला समूहों के सशक्तीकरण के आधार-स्तंभ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. With construction of toilets being only one part of the solution for a clean India, it is time that the Swachh Bharat Mission puts more emphasis on the other facets as well. Discuss. **(250 words) 15**

शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत के समाधान का केवल एक भाग है, अतः अब समय आ गया है कि स्वच्छ भारत मिशन अन्य पहलुओं पर भी अधिक बल दे। चर्चा कीजिए।

भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत अभियान' (CIC) शुरू किया गया था।

इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से प्राथमिक उद्देश्य शौचालयों का निर्माण था। ताकि खुले में शौच से मुक्ति मिल सके।

व्यवहार परिवर्तन (BC) एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) की मदद से इसमें सराहनीय सफलता मिली है। वर्तमान में स्वच्छता कवरेज ~~95~~ लगभग 95% से ऊपर है।

आशा है कि गांधीजी को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

150 वीं जयंती (2 oct. 2019) तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

इसीलिए अब समय आ गया है कि मिशन के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए :—

- ठोस अपशिष्ट निपटान (SWM) एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर कचरे का शत-प्रतिशत समाधान हो जाए तो भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

- इसके अलावा स्वच्छता की आदतों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे - खाना खाने से पूर्व साबुन हाथ धोना।

- मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन भी वर्तमान समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय की आवश्यकता है। अनु. 21 सभी को गरिमापूर्ण जीवन का

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकार देता है।

- इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (CTP) की स्थापना हेतु सरकार व निजी क्षेत्र के तहत "सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल" की आवश्यकता है।

- इसके साथ ही आत्म गौरव, आत्माभिमान की भावना का जागरण भी अवश्य होना चाहिए।

समग्रतः अब खुले में शौच से मुक्ति से आगे बढ़कर सम्पूर्ण स्वच्छ भारत फलक पर कार्य करना स्वच्छ भारत वर्तमान भारत मिशन का लक्ष्य होने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlight the salient features of Mission Indradhanush. What are the challenges that the mission is facing in its implementation? Suggest measures to address these challenges for progressing towards full immunization coverage. **(250 words) 15**

मिशन इन्द्रधनुष की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यान्वयन में मिशन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? संपूर्ण टीकाकरण प्राप्ति की दिशा में प्रगति करने हेतु इन चुनौतियों को दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

संपूर्ण टीकाकरण के उद्देश्य से वर्ष 2014 में 'मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत की गई ताकि 'स्वस्थ भारत' का निर्माण किया जा सके।

मिशन इंद्रधनुष की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

- गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण।
- 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण (वर्ष 2020 तक)।
- मूल रूप से 7 बीमारियों हेतु टीका था — डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इसके 5 अन्य बीमारियों के टीकों यथा जापानी इंसेफेलाइटिस, खसरा इत्यादि को भी शामिल किया जाता है।

मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन में निम्नांकित चुनौतियाँ हैं :-

- लोगों की धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताएँ टीकाकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं।
- स्टॉक के परिरक्षण हेतु पर्याप्त अवसंरचना का अभाव।
- कुशल मानव संसाधन का अभाव।
- जन-जागरूकता का अभाव।
- ग्रामीण व सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचने में भौगोलिक बाधाएँ
- प्रभावी फीडबैक एवं मॉनीटरिंग तंत्र का

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अभाव ।

चुनौतियों के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय हैं:—

⇒ कुशल मानव संसाधन हेतु प्रशिक्षण ।

⇒ निजी क्षेत्र का सहयोग।

⇒ eVIN जैसे आधुनिक स्टॉक भण्डारण पद्धति का उपयोग ।

⇒ प्रगति (PRAGATI) जैसे ई-गवर्नेंस मॉडल की मदद से निगरानी ।

⇒ सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का आदान-प्रदान किया जाए ।

⇒ नागरिक समाज, NGO, सोशल मीडिया की मदद से लोगों में जनजागरूकता फैलाना ।

सारांशतः स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु मिशन इंद्रधनुष का सफल कार्यान्वयन समय की आवश्यकता है; तभी न्यू इंडिया का सपना साकार होगा ।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Assess the importance of skilling in light of changing economic and demographic structure in India. In this regard, how far has the Skill India Mission succeeded in its mandate. **(250 words) 15**

भारत में बदलती आर्थिक और जनसांख्यिकीय संरचना के आलोक में कौशल सृजन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस संबंध में, स्किल इंडिया मिशन अपने अधिदेश में कितना सफल रहा है।

वर्तमान चौथी औद्योगिक क्रांति एवं वैश्वीकरण के युग में कौशल सृजन महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत में 'यूथ डवलपमेंट इंडेक्स-2016' के अनुसार 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है; वहीं इसी तरह नवीन तकनीकी बदलावों (यथा AI, IoT, रोबोटिक्स etc) के कारण आर्थिक संरचना में भी बदलाव आ रहे हैं।

इसीलिए कौशल सृजन का महत्व है -

जनसांख्यिकी लाभांश
⇓
कार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत
⇓
यदि जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल से युक्त है तो

⇓
वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिक उत्पादन
⇓
GDP की वृद्धि

लेकिन अगर जनसंख्या का यह भाग कौशलयुक्त, स्वास्थ्य से पूर्ण व शिक्षित नहीं है तो यही जनसंख्या देश के संसाधनों पर बोझ बन जाएगी और बेरोजगारी, अपराध इत्यादि में वृद्धि होगी।

इसी लिए भारत की युवा आबादी को कौशलयुक्त करने के उद्देश्य से 'स्किल इंडिया मिशन' शुरू किया गया।

- मिशन ने दो प्रकार से मदद की है:—
- (प्रथम) → उन लोगों को औपचारिक प्रशिक्षण दिया है, जो डिग्री रखते हैं परंतु कुशल नहीं है।

- द्वितीय - उन लोगों को प्रमाणपत्र दिए हैं, जो कुशल हैं लेकिन आवश्यक योग्यता के अभाव में उन्हें रोजगार देने में कंपनियां एवं नियोक्ता हिचकिचाते हैं।

लेकिन प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोगों का नवीन श्रमबल में शामिल हो जाना नवीन चुनौती पैदा करता है। इसीलिए कौशल प्रशिक्षण की मांग व आपूर्ति में संतुलन की जरूरत है। (ध्यातव्य है NSSO के PLFS 2017-18 में बेरोजगारी दर = 6.1%)

कुल मिलाकर वर्तमान संक्रमण-कालीन समय में कौशल प्रक्रियों को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने की जरूरत है ताकि भावी पीढ़ियों को कौशलयुक्त किया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. What according to you are the reasons that motivated India to create a dedicated Indo-Pacific division in the MEA recently? Also, highlight the challenges for India in the Indo-Pacific region. **(250 words) 15**

आपके अनुसार वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने हाल ही में भारत को MEA के तहत एक समर्पित भारत-प्रशांत प्रभाग सृजित करने के लिए प्रेरित किया? साथ ही, भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए।

भारत-प्रशांत शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा किया गया।

निम्नांकित कारणों ने भारत को MEA के तहत एक समर्पित भारत-प्रशांत प्रभाग सृजित करने हेतु प्रेरित किया है:—

- चीन की 'सलामी स्लाइसिंग' एवं विस्तारवादी नीतियों के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा यह कदम उठाया गया है।

- अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत, जापान के चतुष्कोणीय गठबंधन 'QUAD' (क्वाड) का भी समर्थन भारत का हित है।

- भारत की विदेश नीति में कमिक रचनात्मक परिवर्तन।

- इसके अलावा चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' तथा 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) पहल के तहत भारत को घेरने की कोशिश। फलतः भारत में नूतन प्रतिरोधीय कदम उठाने हेतु आगे आना है।

भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष निम्नांकित चुनौतियाँ हैं! —

- चीन द्वारा भारत को बाहर से घेर लेना। उदा० के लिए जिबूती, ग्वादर, माले, हंबनटोटा, सितवे बंदरगाहों का विकास।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन भारत द्वारा का बदला (चीनी, सबांग)

- क्षेत्रीय पड़ोसियों यथा बांग्लादेश, मालदीव, म्यानमार इत्यादि को विश्वास में लेना।
- अमेरिकी नीति में स्थिरता का अभाव।
- जापान महत्वा लेकिन द० कोरिया व जापान का परस्पर उलझाव व संघर्ष।
- समुद्री डकैती जैसी अन्य मुद्दे भी भारत का ध्यान भंग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र हेतु बहुआयामी एवं समग्र रणनीतियों की आवश्यकता है, जो यथार्थवाद पर आधारित हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. For SCO to become a successful regional grouping, it has to overcome bilateral differences between its members and their respective geopolitical calculations. Comment. Also, discuss the role that SCO can play in enhancing India's interest in the Eurasian region. **(250 words) 15**

SCO को एक सफल क्षेत्रीय समूह बनने हेतु, अपने सदस्यों के मध्य के द्विपक्षीय मतभेदों और उनके संबंधित भू-राजनीतिक अपेक्षाओं से उबरना होगा। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ाने में SCO द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक अंतः सरकारी संगठन है जो यूरेशिया के सदस्य देशों के भू राजनीतिक एवं कल्याण हेतु कार्यरत है।

SCO
- स्थापना 2001 AD
- मुख्यालय बीजिंग
- सदस्य देश: रूस, चीन, भारत, पाक, कजाकिस्तान, किर्गि, ताजि, उज्बेकिस्तान
- 19वां सम्मेलन - बिश्केक

SCO की सफलता सदस्य देशों के द्विपक्षीय मतभेदों एवं भू-राजनीतिक अपेक्षाओं से उबरना है —

⇒ भारत व चीन सहित चीन व रूस व अन्य मध्य यूरेशियाई देशों के सीमा विवादों का निपटान SCO हेतु आवश्यक है। इस हेतु निरंतर संवाद की जरूरत है। (भारत + पाक भी)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ सदस्य देशों अपने बाजारों को व्यापार घाटा उठाने वाले देशों हेतु खोलना भी जरूरी है।

⇒ इसके 'विस्तारवादी नीतियों' का परित्याग एवं संप्रभुता का सम्मान भी SCO की सफलता हेतु जरूरी शर्त है।

⇒ इसके अलावा संसाधनों के उल्लंघन संबंधी द० चीन सागर में उत्पन्न विवादों का समाधान भी जरूरी है।

यूरेशिया क्षेत्र (यूरोप + एशिया) में भारत के हितों को बढ़ाने में SCO की भूमिका :—

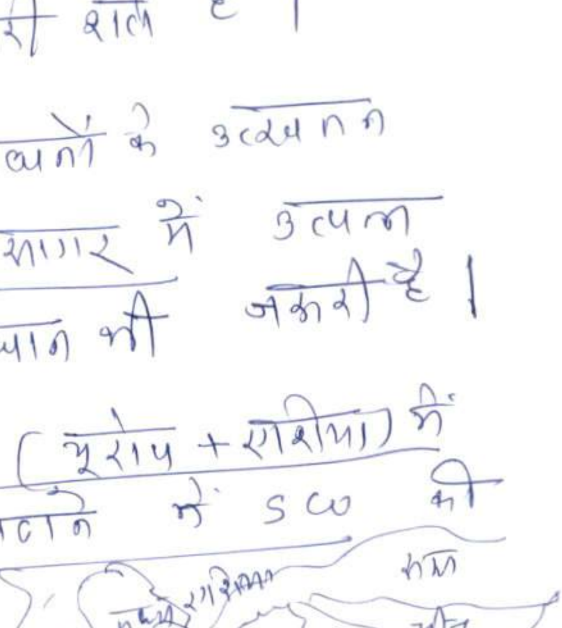

(1) ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएँ भारत के लिए SCO को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

(2) यूरेशियाई क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज में भारतीय कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3 • रोमिंग के माध्यम से भारत चाबहार खाड़ी के पास एवं विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण कर सकता है।

(4) आतंकवाद से प्रशासिका ई जैसा भी पीड़ित है। अतः भारत भी इन देशों के साथ सहयोग करके आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। इस हेतु SCO का RATS (Regional Anti Terrorism Structure) एक महत्वपूर्ण मंच है।

(5) SCO उग्रवाद, अलगाववाद एवं चरमपंथ को रोकने हेतु कार्यरत है।

कुल मिलाकर SCO में निरंतर संवाद एवं सदस्यों का सहयोगपूर्ण रवैया ही इस संगठन को दीर्घजीवी बनाएगा।